रमन

बनाम

उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड एवं अन्य

(सिविल अपील सं. 11466/2014)

17 दिसंबर, 2014

[वी. गोपाल गौड़ा और सी. नागप्पन, न्यायाधिपतिगण]

विद्युत अधिनियम, 2003 धारा 68- बिजली का झटका- मुआवजा- चार साल का लड़का बिजली का झटका लगने से हुई दुर्घटना में 100% स्थायी विकलांगता का सामना करना पड़ा- लड़के ने सभी सुविधाएं खो दीं और जीवन भर एक मृत लकड़ी बन गया- उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश द्वारा 60 लाख रुपये का मुआवजे का पंचाट- 30 लाख रुपये एक राष्ट्रीयकृत बैंक में सावधि खाते में किए जाने हैं, दावेदार के नाम पर संयुक्त खाते में, जो वयस्क होने पर दावेदार को उपलब्ध होगा, और यदि वह जीवित नहीं रहता है, तो जमा राशि प्रतिवादीगणो को वापस कर दी जाएगी-शेष राशि रु. 30 लाख कॉर्पस फंड के सावधि जमा खाते में जमा करने होंगे, जिसमें से रुपये 20,000/- प्रतिमाह का ब्याज दावेदार को खर्च के लिए भुगतान किया जाएगा- वकील द्वारा रियायत पर खंडपीठ ने मासिक राशि घटाकर रु. 10,000/- की- अपील पर, अभिनिर्धारित किया: एकल न्यायाधीश द्वारा दिया गया मुआवजा बहाल किया गया- हालांकि, एकल न्यायाधीश का निर्देश है कि यदि दावेदार वयस्क होने के समय जीवित नहीं है, तो जमा की गई राशि प्रतिवादी को वापस कर दी जाएगी, खारिज किया क्योंकि यह कानूनी और वैध नहीं है- एक बार जब अदालत द्वारा मुआवजा राशि दे दी जाती है, तो यह दावेदार/अपीलकर्ता को मिलनी चाहिए और उसके निधन के बाद, उसके

कानूनी उत्तराधिकारियों या प्रतिनिधि को- राशि के भुगतान के तरीके के संबंध में अपीलकर्ता को निर्देश जारी किए गए हैं।

न्यायालय ने ने अपील स्वीकार करते हुए, अभिनिर्धारित किया :

1.1 उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश के फैसले में 60 लाख रूपये का मुआवजा दिया गया, जिसमें से 30 लाख जमा करने थे, अपीलकर्ता के नाम पर संयुक्त रूप से उसके माता-पिता प्राकृतिक अभिभावक के रूप में और मुख्य अभियंता या उसके नामित व्यक्ति जो प्रतिवादी-निगम का प्रतिनिधित्व करते हैं, उसके वयस्क होने तक एक राष्ट्रीयकृत बैंक में सावधि जमा खाते में जमा कराने थे, न्यायसंगत और उचित है, लेकिन हमें विद्वान एकल न्यायाधीश के फैसले के उस हिस्से को अपास्त करना होगा, जिसमें निर्देश दिया गया था कि यदि वह जीवित रहता है, तो उसे राशि निकालने की अनुमति दी जाती है, अन्यथा जमा राशि उत्तरदाताओं को वापस कर दी जाएगी क्योंकि वह कानूनी नहीं है और इस कारण से वैध नहीं है कि एक बार मुआवजे की राशि अदालत द्वारा दी जाती है, यह दावेदार/अपीलकर्ता को मिलनी चाहिए। इसलिए, पीड़ित/दावेदार कानूनी तौर पर अपने पक्ष में मुआवजा पाने के हकदार हैं। यदि दावेदारों की मृत्यु हो जाती है, तो उनके संबंधित धर्म का उत्तराधिकार अधिनियम पीड़ितों/दावेदारों या कानूनी प्रतिनिधियों के कानूनी उत्तराधिकारियों द्वारा वसीयत दस्तावेज के अनुसार ऐसी संपत्ति पर उत्तराधिकार के लिए लागू होगा, यदि वे अपनी इच्छा का संकेत देते हुए वसीयत को निष्पादित करना चुनते हैं कि ऐसा कौन है जिसको कि उनकी मृत्यु के बाद संपत्ति चली जाएगी। [पैरा 19][863-डी-एच; 864-ए]

1.2 शेष मुआवजा राशि रु. तीस लाख रमन के माता-पिता और प्रतिवादी-निगम का प्रतिनिधित्व करने वाले इंजीनियर-इन-चीफ या उनके नामांकित व्यक्ति की संयुक्त संरक्षकता के तहत अपीलकर्ता (नाबालिग) के नाम पर एक सावधि जमा खाते में

राष्ट्रीयकृत बैंक में कॉर्पस फंड के रूप में 30 लाख रुपये जमा किए जाने हैं। जिसमें से रु. 20,000/- प्रति माह ब्याज देय है। विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश के उप-पैरा (vi) में बताए गए खर्चों के प्रति, यह नहीं कहा जा सकता है कि यह उच्च स्तर पर है, लेकिन हमारे विचार में, दिए गए मुआवजे की उक्त राशि कम है और उचित नहीं है। अपीलकर्ता द्वारा झेली गई 100% स्थायी विकलांगता की प्रकृति के संबंध में, यह बहुत अधिक होनी चाहिए थी क्योंकि अपीलकर्ता को देखभालकर्ता, इलाज, शुल्क स्थाई सहायता की आवश्यकता है क्योंकि वह वैवाहिक जीवन की पीड़ा और हानि से पीड़ित है, जिसकी नुकसाल की भरपाई उच्च न्यायालयके एकल न्यायाधीश द्वारा दिलाई गई मुआवजा राशि से नहीं की जा सकती है। इसलिए, मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, इस संबंध में विद्वान एकल न्यायाधीश के फैसले को बहाल करना उचित और उचित होगा और हम मानते हैं कि उक्त निर्णय में निहित निर्देश ऊपर बताई गई सीमा तक उचित हैं। खंडपीठ को अपने अपीलीय क्षेत्राधिकार का प्रयोग करते समय अपीलकर्ता की ओर से वकील द्वारा प्राप्त कथित अपेक्षित निर्देशों को स्वीकार नहीं करना चाहिए था और इसे विज्ञापन के रूप में मानना चाहिए था और एकल न्यायाधीश के आदेश में प्रदान की गई राशि को संशोधित करना चाहिए था जो पूरी तरह से अनुचित है और इसलिए, यह कानून की दृष्टि से टिकाऊ नहीं है क्योंकि यह उत्तरदाताओं की ओर से लापरवाही के लिए उचित और उचित मुआवजे का कानूनी अधिकार प्राप्त करने के अपीलकर्ता के अधिकार को प्रभावित करेगा। [पैरा 20][864-डी-एच 865-ए]

महाप्रबंधक, केरल राज्य सड़क परिवहन निगम, त्रिवेन्द्रम बनाम सुसम्मा थॉमस और अन्य (1994) 2 एससीसी 176; सरला दीक्षित और अन्य बनाम बलवंत यादव और अन्य (1996) 3 एससीसी 179: 1996 (3) एससीआर 30; यूपी राज्य सड़क परिवहन निगम एवं अन्य बनाम लोक चंद्र और अन्य (1996) 4 एससीसी 362: 1996

(2) पूरक एससीआर 443; यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड और अन्य बनाम पेट्रीसिया जीन महाजन और अन्य 2002 (6) एससीसी 281:2002 (3) एससीआर 1176; अबाती बेजबरूआ बनाम उप महानिदेशक, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण एवं अन्य (2003) 3 एससीसी 148: 2003 (1) एससीआर 1229; सरला वर्मा एवं अन्य बनाम दिल्ली परिवहन निगम और अन्य (2009) 6 एससीसी 121:2009 (5) एससीआर 1098; डॉ. बलराम प्रसाद बनाम कुणाल साहा (2014) 1 एससीसी 384: 2013 (12) एससीआर 30; रेखा जैन बनाम नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (2013) 8 एससीसी 389 - संदर्भित किया गया।

फाउलर बनाम ग्रेस (1970) 114 सोल जो 193 (सीए) - संदर्भित किया गया।

प्रकरण कानूनी संदर्भ:

(1994) 2 एससीसी 176	संदर्भित किया गया	पैरा 8
1996 (3) एससीआर 30	संदर्भित किया गया	पैरा 8
1996 (2) पूरक एस. सी. आर. 443	संदर्भित किया गया	पैरा 8
2002 (3) एससीआर 1176	संदर्भित किया गया	पैरा 8
2003 (1) एससीआर 1229	संदर्भित किया गया	पैरा 8
2009 (5) एससीआर 1098	संदर्भित किया गया	पैरा 17
2013 (12) एससीआर 30	संदर्भित किया गया	पैरा 17
(2013) 8 एस. सी. सी. 389	संदर्भित किया गया	पैरा 18

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार : सिविल अपील संख्या 11466/2014

लैटर पेंटेंट अपील संख्या 14046/2012 में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय, चंडीगढ के निर्णय एवं आदेश दिनांक 30-10-2013 से।

सुशील के. जैन, वरिष्ठ अधिवक्ता, नितिन जैन, सुश्री अनीशा जैन, डॉ. श्रीमती विपिन गुप्ता, अधिवक्तागण, अपीलार्थी के लिए

नरेंद्र हुड्डा, एएजी, एस. एस. हुड्डा, सुश्री बानो डी., मनोज श्योराण, कमल मोहन गुप्ता, अधिवक्तागण, प्रतिवादीगण के लिये।

न्यायालय का निर्णय वी. गोपाल गौड़ा, न्यायाधिपति द्वारा दिया गया था।

1. अनुमति प्रदान की गई।

2. अपीलकर्ता, ने अपने प्राकृतिक अभिभावक पिता मनोज कुमार के माध्यम से प्रतिनिधित्व करते हुए चंडीगढ़ में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय की खंडपीठ द्वारा लेटर्स पेटेंट अपील संख्या 1631/2013 अंतर्गत सिलिव रिट याचि<ा नंबर 114046/2012 में पारित निर्णय और आदेश दिनांक 30.10.2013 पर सवाल उठाते हुए, यह अपील दायर की है।

3. संक्षिप्त तथ्य यहां बताए गए हैं:

अपीलकर्ता, एक चार वर्षीय लड़के की 03.11.2011 को उसके घर की छत पर खुले पड़े नंगे बिजली के तार के सीधे संपर्क में आने से करंट लग गया था। घटना के तुरंत बाद, लड़के को प्राथमिक उपचार के लिए हरियाणा के पानीपत में नजदीकी आर.एम.आनंद अस्पताल ले जाया गया, जहां से उसे पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, रोहतक रेफर कर दिया गया। अंतिम उपचार नई दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में किया गया, जहां डॉक्टरों के पास उसके दोनों हाथों को बांह के गड्ढे तक और बाएं पैर को घुटने तक हटाकर ट्रिपल विच्छेदन करने के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं बचा था क्योंकि गंभीर चोटें इलाज योग्य नहीं थीं। 08.02.2012

को, अपीलकर्ता को 100% स्थायी विकलांगता प्रमाणित करते हुए विकलांगता प्रमाण पत्र जारी किया गया था।

4. अपीलकर्ता की ओर से कहा गया है कि इस दुखद घटना से पहले, 16.08.2011 को अपीलकर्ता के पिता ने अन्य पड़ोसियों के साथ लोहे के एंगल को आवासीय क्षेत्र के आसपास से हटाने के लिए एक प्रतिनिधित्व के माध्यम से एसडीओ, छाजपुर, पानीपत यानी प्रतिवादी नंबर 3 से संपर्क किया था। क्योंकि यह घनी आबादी वाले लगभग 40 से 60 परिवारों के जीवन को खतरे में डालता है। लेकिन उनकी ओर से कोई कार्रवाई नहीं की गयी।

5. अपीलकर्ता ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत एक रिट याचिका दायर करके उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया, जिसमें उत्तरदाताओं से की ओर से लापरवाही के कारण मुआवजे की मांग की गई, जो कि दुखद बिजली के झटके के परिणामस्वरूप अपीलकर्ता का तीन बार विच्छेदन हुआ।

6. उक्त रिट याचिका का उत्तरदाताओं द्वारा एक लिखित बयान दाखिल करके विरोध किया गया, जिसमें लगाए गए आरोपों से इनकार करते हुए कहा गया कि घर की छत पर पाया गया लोहे का एंगल प्रतिवादी बिजली विभाग के किसी भी कर्मचारी द्वारा नहीं लगाया गया था। उत्तरदाताओं द्वारा यह कहा गया है कि अपीलकर्ता के पिता को घर की छत पर स्वयं इंसुलेटर स्थापित करने के लिए दोषी ठहराया गया था, जिस पर हाई टेंशन तार को दूर रखने के लिए खड़ा किया गया था ताकि ईंट और नश्वर को छू न सके। इसलिए, न तो प्रथम प्रतिवादी-उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड, और ना ही इसके कर्मचारियो को उस दिन हुई दुर्घटना के लिए जिम्मेदार या जवाबदेह ठहराया जा सकता है, अपीलकर्ता के पक्ष में दिए जाने वाले नुकसान या मौद्रिक मुआवजे की बात तो दूर है।

7. उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश ने भारतीय विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 68 (संक्षेप में "अधिनियम") और विद्युत नियम, 1956 के नियम 91 (संक्षेप में "नियम") को लागू किया, जो सड़क या सार्वजनिक स्थान या किसी उपभोक्ता के परिसर के किसी भी हिस्से पर खड़ी की गई ओवरहेड विद्युत लाइनों के लिए सुरक्षा और सुरक्षात्मक उपकरण प्रदान करने की प्रक्रिया निर्धारित करता है और यह अनिवार्य है कि लाइन को टूटने की स्थिति में विद्युत रूप से हानिरहित बनाने के लिए इंस्पेक्टर द्वारा अनुमोदित उपकरण के साथ उन्हें संरक्षित किया जाएगा।

8. उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश ने नियमों के नियम 29, 44 और 46 का भी हवाला दिया, जो वैधानिक प्रकृति के हैं, जिनके लिए बिजली अधिकारियों को उनके द्वारा बनाए रखी गई लाइनों का समय-समय पर निरीक्षण करने और दुर्घटना को रोकने के लिये और लाइनों का रखरखाव के सभी सुरक्षा उपाय करने की आवश्यकता होती है कि आम जनता की जान-माल की सुरक्षा हो सके। विद्वान एकल न्यायाधीश ने मुआवजा देने के मामलों में इस न्यायालय द्वारा घोषित कानून की स्थिति पर विचार किया है, विशेष रूप से, बिजली के झटके के मामलों में, और राज्य विद्युत बोर्ड के विरूद्ध और दावेदार के पक्ष में मुआवजा देने, में "सख्त दायित्व" और परिणामी लापरवाही के सिद्धांत को माना है। इस न्यायालय और विभिन्न उच्च न्यायालयों जैसे मद्रास, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, केरल और गुजरात के उच्च न्यायालयों ने असाधारण और अपीलीय क्षेत्राधिकार का प्रयोग करते हुए बिजली के झटके के पीड़ितों को मुआवजा दिया है, और माना है कि बिजली बोर्ड आपूर्ति कंपनियां अधिनियम के प्रावधानों के तहत एहतियाती कदम उठाने के लिए कर्तव्य से बाध्य है। इसलिए, विद्वान एकल न्यायाधीश ने बिजली प्राधिकरण- पहले प्रतिवादी को, दावेदार को मुआवजा देने के लिए उत्तरदायी माना है, इस तथ्य के बावजूद कि उपभोक्ता द्वारा एहतियाती उपाय अपनाते हुये नुकसान से बचा जा सकता था। उच्च न्यायालय के

विद्वान एकल न्यायाधीश ने दावेदार के पक्ष में न्यायसंगत और उचित मुआवजा निर्धारित करने और देने के लिए इस न्यायालय के साथ-साथ मोटर वाहन अधिनियम के तहत दिए गए उपरोक्त उच्च न्यायालयों के विभिन्न निर्णयों का उल्लेख किया है, अर्थात; महाप्रबंधक, केरल राज्य सड़क परिवहन निगम, त्रिवेन्द्रम बनाम सुसम्मा थॉमस और अन्य", सरला दीक्षित और अन्य बनाम बलवंत यादव और अन्य., उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम और अन्य बनाम त्रिलोक चंद्र और अन्य., यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड और अन्य बनाम पेट्रीसिया जीन महाजन और अन्य और अबाती बेज़बरुआ बनाम उप महानिदेशक, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण और अन्य, एम.वी. अधिनियम की अनुसूची में निर्दिष्ट गुणक विधि को लागू करते हुये।

9. विद्वान एकल न्यायाधीश ने अपीलकर्ता को मुआवजा दिया और प्रतिवादी को निर्देश जारी किए जो (xiii) खंड/पैराग्राफ में चलते हैं। उच्च न्यायालय की खंडपीठ द्वारा अपने फैसले में संशोधन से पहले, विद्वान एकल न्यायाधीश के फैसले के प्रासंगिक पैराग्राफ संख्या (v) और (vi) नीचे दिए गए हैं:

"V) नाबालिग रमन के वित्तीय और वित्तीय भविष्य को सुरक्षित करने के लिए, यह निर्देशित किया जाता है कि प्रतिवादी-निगम उसे जीवन के आनंद की हानि, आघात सहने और कार्रवाई करने के लिए तुरंत 30 लाख रुपये का मुआवजा उपेक्षा और दूसरों पर निर्भरता से बचाव, भविष्य की रोजगार क्षमता की हानि और इस सब की पीड़ा, दर्द और मानसिक आघात का सामना करने के लिये देगा और एक अपूरणीय घटना से पीड़ित होना जारी रहेगा जिसने एक परिवार के जीवन को पूरी तरह से बदल दिया है। यह राशि 21 वर्ष की आयु तक पहुंचने पर ब्याज सहित उपलब्ध कराई जाएगी, जो भविष्य के लिए वित्तीय सुरक्षा और बिल्डिंग ब्लॉक के रूप में कार्य करेगी। यह राशि याचिकाकर्ता (नाबालिग) के नाम पर रमन के माता-पिता और प्रतिवादी-निगम का प्रतिनिधित्व करने वाले इंजीनियर-इन-चीफ या उसके नामांकित व्यक्ति की संयुक्त

संरक्षकता के तहत एक राष्ट्रीयकृत बैंक में, एक सावधि जमा खाते में जमा की जाएगी, विशेष तौर पर स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय, चंडीगढ़ की शाखा में। इस आदेश की प्रमाणित प्रति प्राप्त होने के 60 दिनों के भीतर राशि जमा करने का निर्देश दिया गया है, अन्यथा बैंक में जमा होने तक राशि पर 8.5% ब्याज लगेगा, जहां मूल राशि के बाद सावधि जमा के लिए बैंक दरों पर समय- समय पर ब्याज मिलेगा। हालाँकि, इस मद के तहत दी जाने वाली राशि केवल नाबालिग रमन को वयस्क होने यानी 21 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर ही उपलब्ध होगी। यदि नाबालिग रमन वयस्क होने तक जीवित नहीं रहता है, तो यह राशि सभी अर्जित ब्याज के साथ प्रतिवादी-निगम को वापस कर दी जाएगी और किसी तीसरे पक्ष या रमन के माता-पिता या भाई-बहन द्वारा इस पर कोई दावा नहीं किया जाएगा। इससे यह सुनिश्चित होगा कि बच्चे के वयस्क होने तक उसे महत्व दिया जाए और उसकी देखभाल की जाए।

vi) चूंकि 30 लाख रुपये की उपरोक्त राशि याचिकाकर्ता के उपयोग के लिए पहुंच से बाहर रहेगी, इसलिए उसे भुगतान किए गए देखभालकर्ताओं/परिचारकों या ऐसे खर्चों के बराबर पारिवारिक सहायता/श्रम और अन्य नंगे और विविध खर्चों के लिए अपने दैनिक खर्चों को पूरा करने के लिए चालू आय की आवश्यकता होगी, जो वर्तमान में जीवन भर के लिए लगभग 20,000/- रुपये से अधिक प्रति माह निर्धारित है। प्रति माह रु. 20,000/- का ब्याज अर्जित करने के लिए लंबी अवधि की सावधि जमा पर मौजूदा दरों के अनुसार 8.5% की दर से ब्याज अर्जित करने के लिए बैंक में 30 लाख रुपये का निवेश करना आवश्यक है। इसलिए, निर्देश (v) में दिए गए 30 लाख रुपये के अलावा, प्रतिवादी-निगम अतिरिक्त मुआवजा देगा और जमा करेगा। 30 लाख रुपये की राशि को उसी बैंक में एक अलग ब्याज वाले खाते में उसी संयुक्त संरक्षकता व्यवस्था के तहत रखा जाना चाहिए जैसा कि बिंदु संख्या (v) में निर्देशित है। यह एक ब्याज

अर्जित करने वाला खाता होगा जिसमें प्रार्थी की रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करने के लिए ब्याज आय उपलब्ध होगी। इस प्रकार अर्जित ब्याज को नाबालिग रमन के नाम पर उसी शाखा में खोले जाने वाले एक अलग बचत बैंक खाते में स्थानांतरित कर दिया जाएगा, जिसे माता-पिता द्वारा संयुक्त रूप से संचालित किया जाएगा, जो याचिकाकर्ता को नियमित मासिक आधार पर देय होगा, जिसे बच्चे की देखभाल के लिए लागू किया जाएगा। माता-पिता, उसके शैक्षिक खर्च, पौष्टिक भोजन, परिचारकों/देखभाल करने वालों की देखभाल करने वालों की लागत, दिन-ब-दिन उसकी सेवा करना आदि। 30 लाख रुपये की उपरोक्त राशि जिसमें से याचिकाकर्ता के लिए महीने-दर-महीने ब्याज का उपयोग किया जाएगा, की भी अनुमति नहीं होगी याचिकाकर्ता के 21 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, इस न्यायालय से आदेश प्राप्त किए बिना, यदि परिस्थितियां ऐसी मांग करती हैं, निर्देशानुसार मासिक ब्याज को छोड़कर, किसी भी उद्देश्य के लिए वापस लिया जा सकता है। स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय, चंडीगढ़ की शाखा नाबालिग के नाम पर उक्त बचत बैंक खाता खोलेगी; माता और पिता के संरक्षण में और उक्त बचत बैंक खाते को याचिकाकर्ता के निवास के निकटतम शाखा में स्थानांतरित करें और बैंक हर महीने उस पर अर्जित ब्याज को पानीपत शाखा में उक्त बचत खाते में भेज देगा, जब तक कि स्वतः नवीनीकृत न हो जाए। याचिकाकर्ता 21 वर्ष की आयु तक पहुँच जाता है। इस आदेश की प्रमाणित प्रति प्राप्त होने के 60 दिनों के भीतर राशि जमा करने का निर्देश दिया गया है, अन्यथा बैंक में जमा होने तक राशि पर 8.5% ब्याज लगेगा, जहां मूल राशि के बाद समय-समय पर सावधि जमा के लिए बैंक दरों पर ब्याज मिलेगा।

अपीलकर्ता के पक्ष में विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा उपरोक्त शर्तों में दिए गए मुआवजे के अलावा, भविष्य में किसी भी दुर्भाग्यपूर्ण विद्युत दुर्घटना को रोकने के लिए इसके अनुपालन के लिए उत्तरदाताओं को कुछ अन्य निर्देश भी दिए गए थे।

10. विद्वान एकल न्यायाधीश के निर्णय और आदेश दिनांक 02.07.2013 से व्यथित होकर, प्रतिवादीगणो ने विभिन्न आधारों का आग्रह करते हुए उच्च न्यायालय में एलपीए दायर किया और इसे अपास्त किये जाने की प्रार्थना की। उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने 30.10.2013 को एक गूढ़ आदेश पारित किया, जिसमें अपीलकर्ता की ओर से वकील द्वारा दी गई कथित रियायत के आधार पर उत्तरदाताओं द्वारा दायर एलपीए को आंशिक रूप से अनुमति देते हुए कहा गया कि पक्षकारो के विद्वान वकील ने अपेक्षित निर्देश प्राप्त किए गए हैं और उनका मानना है कि त्वरित अपील का निपटारा निम्नलिखित सहमत शर्तों पर किया जाएगा, जो इस प्रकार हैं:-

"(1) आक्षेपित आदेश पक्षकारो द्वारा स्वीकार किया जाता है, इसके बाद निर्दिष्ट संशोधन की सीमा को छोड़कर।

(2) निर्देश के खंड (v) में निर्दिष्ट 30 लाख रुपये की राशि पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय, चंडीगढ़ की शाखा के बजाय स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, पानीपत शाखा में जमा किए जाएंगे।

(3) यह राशि 10 दिनों के भीतर अपीलकर्ताओं को दिए गए खाता संख्या में जमा की जाएगी और उसी उप-पैरा में निहित निर्देशों के अनुसार तुरंत एफडीआर में परिवर्तित की जाएगी;

(4) उप-पैरा (vi) में दिए गए निर्देशों के स्थान पर 10,000/- रुपये प्रति माह की राशि का भुगतान करने का निर्देश दिया जाएगा। हर महीने की 7 तारीख को या उससे पहले, सीधे बैंक खाते में पहले ही सूचित कर दिया जाएगा और ऐसा भुगतान तब तक किया जाता रहेगा जब तक कि नाबालिग 21 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं कर लेता।

11. अपीलकर्ता श्री सुशील कुमार जैन की ओर से विद्वान वरिष्ठ वकील द्वारा यह आग्रह किया गया है कि दुर्भाग्यपूर्ण अपीलकर्ता लड़का या उसके माता-पिता जो कार्यवाही में उसके प्राकृतिक अभिभावक हैं, प्रतिवादियों के साथ उनके वकील की सांठगांठ से अनभिज्ञ थे और जब उन्हें एलपीए में पारित इस आदेश के बारे में पता चला, 27.01.2014 को एक कानूनी नोटिस विश्वास के उल्लंघन और पेशेवर कदाचार के लिये अधिवक्ता अधिनियम 1961 के तहत, उच्च न्यायालय की खंडपीठ के समक्ष बिना उनके या तो मौखिक या लिखित निर्देश में रियायत देते हुये, उनके वकील को भेजा गया था,

इसलिए, अपीलकर्ता ने विभिन्न आधारों का आग्रह करते हुए उच्च न्यायालय की खंडपीठ के आक्षेपित निर्णय और आदेश की शुद्धता पर सवाल उठाते हुए इस अपील के साथ इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है।

12. अपीलकर्ता की ओर से विद्वान वरिष्ठ वकील ने तर्क दिया है कि उच्च न्यायालय की खंडपीठ के आदेश ने विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा दी गई मुआवजा राशि को रुपये 60 लाख से 30 लाख रुपये कम कर दिया है और मासिक भुगतान 20 हजार रूपये 10 हजार रूपये कर दिया है; जब तक वह 21 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं कर लेता, विज्ञापन मद के कारण, जो वास्तव में मनमाना, अनुचित है और सही नहीं है, क्योंकि अपीलकर्ता ने अपने वकील को विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा दिए गए मुआवजे को कम करने के लिए खंडपीठ के समक्ष रियायतें देने के ऐसे निर्देश नहीं दिए हैं।

13. अपीलकर्ता की ओर से विद्वान वरिष्ठ वकील ने आगे आग्रह किया कि उच्च न्यायालय की डिवीजन बेंच को बिजली के झटके से हुई दुर्घटना में अपीलकर्ता को लगी गंभीर चोटों की प्रकृति और दिए गए मुआवजे को ध्यान में रखते हुए मामले की

जांच करने की करने की आवश्यकता थी। विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा उप-पैरा (vi) के तहत बीस हजार रूपये प्रतिमाह के स्थान पर दस हजार रूपये प्रतिमाह के भुगतान की सीमा तक संशोधित नहीं किया जाना चाहिये था। आक्षेपित निर्णय के अनुसार, अपीलकर्ता से वकील द्वारा प्राप्त कथित निर्देशों के आधार पर अपीलकर्ता के पक्ष में दिए गए मुआवजे को कम करके आक्षेपित निर्णय पारित करके अपील का निपटारा किया गया, इसकी कार्रवाई कानून में पूरी तरह से अस्थिर है और इसलिए रद्द किये जाने योग्य है।

14. दूसरी ओर, उत्तरदाताओं की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील श्री नरेंद्र हुडा ने प्रस्तुत किया कि विद्वान वरिष्ठ वकील द्वारा दिए गए मुआवजे में कोई कमी नहीं की गई है, सिवाय इसके कि आक्षेपित निर्णय में पैरा 4 में अपीलकर्ता के मासिक खर्चों के लिए, रूपये 20 हजार के स्थान पर रूपये 10 हजार का उल्लिखित संशोधन किया गया है। जो अपीलकर्ता के अधिकारों को प्रभावित नहीं करेगा और इसलिए, उसने अपील को खारिज करने की प्रार्थना की है क्योंकि यह योग्यता से रहित है।

15. हमने उन पक्षों के विद्वान वरिष्ठ वकील को सुना है जिन्होंने अपने-अपने दावे के समर्थन में अपनी-अपनी दलीलें दी हैं, जिनकी हमारे द्वारा निर्विवाद तथ्यों के संदर्भ में सावधानीपूर्वक जांच की गई है, विशेष रूप से, दोनों हाथों के आर्मपिट तक के विच्छेदन और मामले में प्रस्तुत किए गए डॉक्टर के प्रमाण पत्र के अनुसार बाएं पैर के घुटने तक चोट लगने के कारण अपीलार्थी को 100% स्थायी विकलांगता हो गई है।

16. घटना के समय लड़के की उम्र 5 वर्ष और भारतीय नागरिक की दीर्घायु 70 वर्ष मानते हुए, शेष 65 वर्ष अपीलकर्ता को मानसिक पीड़ा और कठिनाई से पीड़ित होने के लिए आवश्यक हैं। वह वस्तुतः मृत लकड़ी है और इसके अलावा उसे प्रकृति की

पुकार में भाग लेने, बैठने, खड़े होने, चलने और सोने के समय निरंतर दर्द और पीड़ा से गुजरना पड़ता है। उसे जीवन के हर क्षेत्र में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, जो मृत्यु से भी बदतर है। उसका बचपन खो गया, वैवाहिक स्थिति और खुशियाँ खो गईं, जिसकी भरपाई पैसों से नहीं की जा सकती। उसे जीवन भर बड़ी कठिन परीक्षा और पीड़ा से गुजरना पड़ता है। उसे अपने पूरे जीवनकाल में सभी उद्देश्यों के लिए सहायता के लिये एक स्थाई परिचारक की आवश्यकता होती हे, जिसे अपीलकर्ता को औसतन 10 हजार से 15 हजार प्रतिमाह तक भुगतान करना होता है और यह एक कड़वी सच्चाई है कि हमारे देश में जीवनयापन की लागत भी दिन-ब-दिन लगातार बढ़ती जा रही है। मामले के इस पहलू पर अपीलकर्ता को दिए गए मुआवजे को कम करते समय उच्च न्यायालय की खंडपीठ द्वारा विचार किया जाना चाहिए था।

17. उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश ने मामले के इन सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए मुआवजा दिया है और सरला वर्मा और अन्य बनाम दिल्ली परिवहन निगम और अन्य के मामले में दिये गये गुणक विधि के मार्गदर्शक सिद्धांत को लागू किया है। अपीलकर्ता के पक्ष में युक्तियुक्त और उचित मुआवजे की गणना के प्रयोजन के लिए कौन सी विधि हस्तगत प्रकरण में लागू नहीं की जानी चाहिए थी, विशेष रूप से, उत्तरदाताओं की ओर से वैधानिक लापरवाही को ध्यान में रखते हुए, यह देखने के लिए सुरक्षा उपाय प्रदान नहीं किए गए कि बिजली के तार इमारत की छत पर न गिरें, आवासीय क्षेत्र में जनता के जीवन की रक्षा के लिए नियमों का सख्ती से पालन किया जाए। डॉ. बलराम प्रसाद बनाम कुणाल साहा" के मामले में यह न्यायालय चिकित्सकीय लापरवाही के मामले में दावेदार के पक्ष में उचित और उचित मुआवजा देने के लिए गुणक पद्धति का पालन करने से भटक गया है। हस्तगत मामले में भी यही सिद्धांत लागू होगा। उपरोक्त संदर्भित मामले में इस न्यायालय द्वारा निम्नलिखित मामले के कानून का पालन किया जाता है, अपीलकर्ता

के पक्ष में उचित और उचित मुआवजा देने के लिए प्रासंगिक पैराग्राफ यहां निकाले गए हैं:

68..... इंडियन मेडिकल असोसिएशन बनाम वी.पी. शांता में इस कोर्ट की तीन जजों की बेंच का फैसला, जिसमें इस न्यायालय ने एक अन्य मामले में इस विशिष्ट बिंदु पर स्पष्ट रूप से असहमति जताई है जिसमें "चिकित्सा लापरवाही" शामिल थी। उक्त निर्णय में, पैरा 53 में यह माना गया है कि किसी वैध दावे को अस्वीकार करना या किसी पुरस्कार के आकार को मनमाने ढंग से प्रतिबंधित करना दावेदार के साथ काफी अन्याय होगा।

99. गोविंद यादव बनाम न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड में इस न्यायालय ने पैरा 15 पर टिप्पणी की थी जिसे एससीसी पीपी 639-40, इब्राहिम बनाम राजू के पैरा 13 में दोहराया गया था:

"15. रेशमा कुमारी बनाम मदन मोहन में [(2009) 13 एससीसी 422] इस न्यायालय ने दोहराया कि अधिनियम के तहत दिया गया मुआवजा उचित होना चाहिए और उन कारकों की भी पहचान की, जिन्हें मुआवजे की राशि निर्धारित करते समय ध्यान में रखा जाना चाहिए। फैसले के प्रासंगिक अंश नीचे दिए गए हैं:

26. जो मुआवज़ा निर्धारित किया जाना आवश्यक है वह उचित होना चाहिए। जबकि दावेदारों को उनकी निर्भरता के नुकसान के लिए मुआवजा दिया जाना आवश्यक है, इसे अप्रत्याशित लाभ नहीं माना जाना चाहिए। अन्यायपूर्ण संवर्धन को हतोत्साहित किया जाना चाहिए। यह न्यायालय इस तथ्य को भी नजरअंदाज नहीं कर सकता है कि दिए गए मामलों में, उदाहरण के लिए एक मां के इकलौते बेटे की मृत्यु, उसे कभी भी मौद्रिक शर्तों में मुआवजा नहीं दिया जा सकता है।

27. भविष्य की कमाई के संभावित नुकसान के संबंध में मुआवजे के निर्धारण के लिए लागू की जाने वाली आवश्यक पद्धति का प्रश्न, हालांकि, जहां तक संभव हो कुछ सिद्धांतों पर आधारित होना चाहिए। एक व्यक्ति के पास उज्ज्वल भविष्य की संभावना हो सकती है; हो सकता है कि वह तुरंत पदोन्नति का पात्र बन गया हो; तत्काल वेतन संशोधन की संभावना हो सकती थी, जबकि दूसरी (विषम स्थिति) में रोजगार की प्रकृति ऐसी थी कि वह सेवा में जारी नहीं रह सकता था; उसकी पदोन्नति की संभावना, रोजगार की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए दूर या दूरस्थ हो सकती है। इसलिए, किसी भी अदालत के लिए कठोर परीक्षण निर्धारित करना कठिन है जिसे सभी स्थितियों में लागू किया जाना चाहिए। अलग-अलग विचार हैं। कुछ मामलों में यह सुझाव दिया गया है कि किसी प्रकार की परिकल्पना या अनुमान अपरिहार्य हो सकता है। ऐसा हो सकता है।

XXX XXX XXX

46. भारतीय संदर्भ में आश्रितों की शिक्षा और नौकरी की प्रकृति सहित कई अन्य कारकों को ध्यान में रखा जाना चाहिए। बदली हुई सामाजिक परिस्थितियों और वैश्विक परिदृश्य के मद्देनजर, न केवल कर्मचारी की स्थिति, उसकी शैक्षणिक योग्यता को ध्यान में रखकर भविष्य की संभावनाओं को ध्यान में रखना होगा; उसका अतीत के प्रदर्शन के साथ-साथ अन्य प्रासंगिक कारक भी हैं, अर्थात् उच्च वेतन और भत्ते जो इन दिनों निजी कंपनियों द्वारा पेश किए जा रहे हैं। वास्तव में गुणक का निर्धारण करते समय इस न्यायालय ने ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम जशुबेन मामले में कहा था कि महंगाई भत्ता और उसके संबंध में भत्ते, जिनसे परिवार को मासिक लाभ प्राप्त होता, को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए।

47. जिन आकस्मिक मुद्दों पर भी विचार किया जाना है उनमें से एक मुद्रास्फीति है। क्या मुद्रास्फीति को ध्यान में रखने की प्रथा पूरी तरह गलत है? दुर्भाग्य से, अन्य विकसित देशों के विपरीत, भारत में कोई वैज्ञानिक अध्ययन नहीं हुआ है। उम्मीद है कि बढ़ती महंगाई के साथ ब्याज दरें भी बढ़ेंगी। भारत में ऐसा नहीं होता। इसलिए, यह एक प्रासंगिक कारक हो सकता है जिसे वास्तविक जमीनी हकीकत निर्धारित करने के लिए ध्यान में रखा जा सकता है। हालाँकि, इसके लिए कोई कठोर नियम नहीं बनाया जा सकता।'

101.....उन्होंने मलय कुमार गांगुली के मामले में पैरा 170 में की गई टिप्पणियों पर भी दृढ़ता से भरोसा किया है, जिसमें इस न्यायालय ने इस प्रकार टिप्पणियां की हैं: (एससीसी पृष्ठ 282)

> "170- निर्विवाद रूप से, किसी दुर्घटना से जुड़े मुआवजे का अनुदान अपकृत्य कानून के दायरे में है। यह इंटीग्रम में पुनर्स्थापन के सिद्धांत पर आधारित है। उक्त सिद्धांत यह प्रदान करता है कि क्षति के हकदार व्यक्ति को, जितना संभव हो उतना, वह मिलना चाहिए। धन की राशि जो उसे उसी स्थिति में रखेगी जिस स्थिति में वह होता अगर उसने गलत नहीं किया होता। (लिविंगस्टोन बनाम रॉयाईस कोल कंपनी देखें)"

103.1. निंगम्मा के मामले में, इस न्यायालय ने पैरा 34 पर टिप्पणी की है जो इस प्रकार है: (एससीसी पृष्ठ 721)

> "34..... हमारी सुविचारित राय में किसी पार्टी को 'उचित मुआवजा' पाने से वंचित नहीं किया जाना चाहिए, यदि दावेदार कानून के किसी भी प्रावधान के तहत मामला बनाने में सक्षम है, तो कहने की जरूरत

नहीं है, एमवीए फायदेमंद है और कल्याण कानून। वास्तव में, अदालत कर्तव्यबद्ध है और 'उचित मुआवजा' देने का हकदार है, इस तथ्य की परवाह किए बिना कि दावेदार द्वारा उस संबंध में कोई याचिका दायर की गई थी या नहीं।"

112. दावेदार ने अपनी दलील के समर्थन में निज़ाम इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज बनाम प्रशांत एस.धनंका के [(2009) 2 एससीसी 688] मामले पर भी भरोसा किया है कि यदि कोई मामला बनता है, तो न्यायालय को पर्याप्त मुआवज़ा देना लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए। प्रासंगिक पैराग्राफ इस प्रकार है:

"88. हमें इस बात पर जोर देना चाहिए कि अदालत को पीड़ित की बढ़ी हुई और अनुचित मांगों और विपरीत पक्ष के समान रूप से अस्थिर दावे के बीच संतुलन बनाना होगा कि कुछ भी देय नहीं है। पीड़ित के लिए सहानुभूति नहीं आती है और नहीं आनी चाहिए सही मूल्यांकन करने के तरीके में, लेकिन यदि कोई मामला बनता है, तो अदालत को पर्याप्त मुआवजा देने में आनाकानी नहीं करनी चाहिए। हम जिस 'पर्याप्त मुआवजे' की बात करते हैं, वह कुछ हद तक एक सामान्य नियम होना चाहिए। और चूंकि एक संतुलन बनाना होगा, सभी संबंधित पक्षों को संतुष्ट करना मुश्किल होगा।"

इसके अलावा पैरा 119 में, यह माना गया है...इस न्यायालय ने मुआवजे की मात्रा की गणना और पुरस्कार देने के लिए गुणक प्रणाली के उपयोग को खारिज कर दिया है जो उचित और उचित होना चाहिए। सुसंगत पैराग्राफ यहां उद्धृत किया गया है: (एससीसी पैरा 92)

"92. प्रतिवादी के विद्वान वकील श्री टांडले ने आगे कहा है कि मुआवजे का निर्धारण करने के लिए उचित तरीका गुणक विधि होगी। हमें इस याचिका में बिल्कुल कोई योग्यता नहीं है। शिकायतकर्ता को जिस प्रकार की क्षति हुई है, व्यय उसने जो खर्च किया है और भविष्य में भुगतने की संभावना है और संभावना है कि उसके चुने हुए क्षेत्र में उसका उत्थान अब प्रतिबंधित हो जाएगा, ऐसे मामले हैं जिन पर गुणक पद्धति के तहत ध्यान नहीं दिया जा सकता है।" (जोर दिया गया)

इसके अलावा पैराग्राफ संख्या 121 के तहत, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम पेट्रीसिया जीन महाजन से संबंधित पैराग्राफ इस प्रकार पढ़ा गया: (एससीसी पीपी 295-96, पैरा 20)

"20. अदालत वास्तविकताओं से पूरी तरह से अनभिज्ञ नहीं हो सकती है। दूसरी अनुसूची में गुणक निर्धारित करते समय, अधिकतम आय 40,000 रुपये प्रति वर्ष को ध्यान में रखा गया था, लेकिन इसे उच्च आय के मामलों में निर्धारित गुणक लागू करने के लिए एक सुरक्षित मार्गदर्शिका माना जाता है। लेकिन ऐसे मामलों में जहां आय में अंतर इतना बड़ा है कि वर्तमान मामले में आय 2,26,297 डॉलर है, ऐसी स्थिति में, यह नहीं कहा जा सकता है कि गुणक में कुछ विचलन अस्वीकार्य होगा। इसलिए, लागू करने से विचलन दूसरी अनुसूची में दिए गए गुणक को इस मामले में बनाना पड़ सकता है। पहले बताए गए कारकों के अलावा गुणक की मात्रा भी ध्यान में रखा जाने वाला एक कारक बन जाती है जो इस मामले में 2,26,297 डॉलर तक पहुंचती है, यानी, इसे 30 रुपये की दर से परिवर्तित करने पर लगभग

68 लाख रुपये प्रति वर्ष की राशि मिलती है। भारतीय मानकों के अनुसार यह निश्चित रूप से एक उच्च राशि है। इसलिए, उचित मुआवजे के प्रयोजनों के लिए, भारी मात्रा में गुणक पर कम गुणक लगाया जा सकता है। सुसम्मा थॉमस में की गई टिप्पणियों के अनुसार भी गुणक के आंकड़े में विचलन उचित रूप से स्वीकार्य होगा जहां एक विशिष्ट उदाहरण दिया गया था कि एक व्यक्ति 45 वर्ष की आयु में मर जाता है और उसके माता-पिता के अलावा कोई उत्तराधिकारी नहीं बचता है।" (जोर दिया गया)

इसके अलावा, अनुच्छेद 177 में, इसे इस प्रकार रखा गया था:-

"177. दावेदार की पत्नी के दर्द और पीड़ा के कारण हानि और सुविधाओं की हानि के शीर्षक के तहत, केम्प और केम्प निम्नानुसार लिखते हैं:

"दर्द और पीड़ा" के अंतर्गत क्षति के वादी को पुरस्कार, जैसा कि लॉर्ड स्कर्मन ने लिम पोह चू बनाम कैमडेन और इस्लिंगटन क्षेत्र स्वास्थ्य प्राधिकरण में कहा था, "दावेदार की दर्द के बारे में व्यक्तिगत जागरूकता, उसकी पीड़ा सहने की क्षमता पर निर्भर करता है। तदनुसार, कोई पंचाट उचित नहीं है, यदि और जहाँ तक दावेदार को पीड़ा न हुई हो और उसे दर्द सहने की संभावना न हो, और उसने कष्ट न सहा हो और न ही पीड़ा सहने की संभावना हो, उदाहरण के लिए, क्योंकि वह दुर्घटना में तुरंत और स्थायी रूप से बेहोश हो गया था। इसके विपरीत, जब भी वास्तव में ऐसा कोई नुकसान होता है तो

सुविधाओं के नुकसान के संबंध में हर्जाना देना उचित होता है, भले ही दावेदार को नुकसान के बारे में पता हो।"

XXX XXX XXX

'भले ही दावेदार दुर्घटना के तुरंत बाद अपनी चोटों से मर सकता है, सबूत इस मद के तहत पुरस्कार को उचित ठहरा सकते हैं। सदमे को भी दर्द और पीड़ा के एक घटक के रूप में माना जाना चाहिए और दावेदार की विशेष परिस्थितियाँ उसकी पीड़ा की सीमा के लिए अत्यधिक प्रासंगिक हो सकती हैं.....

किसी विशेष मामले में खोई गई सुविधाओं की प्रकृति और चोट और दर्द पर विचार करके, अदालत को विशेष दावेदार पर प्रभाव का आकलन करना चाहिए। क्षतिपूर्ति का उचित पुरस्कार तय करने में, एक महत्वपूर्ण विचार यह दर्शाता है कि क्या वह उन सुविधाओं से कब तक वंचित रहेगा और दर्द और पीड़ा कब तक सहन की गई है और सहन की जाएगी। यदि यह उसके शेष जीवन के लिए है तो अदालत को नुकसान का आकलन करते समय दावेदार की उम्र और जीवन में उसकी अपेक्षाओं को ध्यान में रखना होगा... (जोर दिया गया)

18. इसके अलावा, रेखा जैन बनाम नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड 8 के मामले में, इस न्यायालय ने पैरा 34 और 35 में, क्षति की मात्रा के संबंध में, निम्नानुसार माना है:

"34.....किसी व्यक्ति को लगी व्यक्तिगत चोटों के लिए भुगतान की जाने वाली क्षति की मात्रा पर निर्णय लेने में, न्यायालय उन सभी विचारों को सुनिश्चित करने के लिए बाध्य है जो पीड़ित की चोटो को क्षतिपूर्ति प्रदान करेंगे। जहां तक पैसा हो सकता है, वह नुकसान जो उसके साथ किए गए गलत के स्वाभाविक परिणाम के

रूप में हुआ है। [के. नरसिम्हा मूर्ति बनाम प्रबंधक, ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड और अन्य]। [आईएलआर 2004 केएआर 2471]

35..... इसलिए, सामान्य सिद्धांत जो व्यक्तिगत चोट के मामलों में क्षति के आकलन को नियंत्रित करना चाहिए वह यह है कि न्यायालय को घायल व्यक्ति को इतनी धनराशि देनी चाहिए जिससे वह उसी स्थिति में आ जाए जिस स्थिति में वह है, यदि उसे चोटें नहीं लगी होतीं तो वह इसमें शामिल होता। लेकिन, यह स्पष्ट है कि पैसे का कोई भी पुरस्कार संभवतः एक घायल व्यक्ति की भरपाई नहीं कर सकता है और टूटे हुए मानव ढांचे को नवीनीकृत नहीं कर सकता है।"

39...मेडियाना में, [1900 एसी 113 (एचएल)] में, इसे पैरा 32 पर रखा गया है जिसे यहां इस प्रकार निकाला गया है

32.... व्यक्तिगत चोट के मामलों में, न्यायालय को लगातार अवसरों और जोखिमों का अनुमान लगाने की आवश्यकता होती है जिन्हें सटीकता से निर्धारित नहीं किया जा सकता है। ऐसा इसलिए है, क्योंकि कानून उन संभावनाओं की उपेक्षा करेगा जो मामूली हैं या जो संभावनाएं अस्पष्ट हैं; अन्यथा, स्थिति की सभी परिस्थितियों को ध्यान में रखा जाना चाहिए, चाहे वे उस भविष्य से संबंधित हों जिसका वादी ने आनंद लिया होता यदि दुर्घटना नहीं हुई होती, या उसकी चोटों के भविष्य और दुर्घटना के बाद उसकी कमाई की शक्ति से संबंधित हो। क्षति किसी चोट या हानि के लिए मुआवज़ा है, यानी, जहां तक धन की प्रकृति स्वीकार करती है, धन के पूर्ण समतुल्य; और कठिनाई या अनिश्चितता किसी मूल्यांकन को नहीं रोकती।' [के. नरसिम्हा मूर्ति बनाम प्रबंधक, ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड और अन्य] [आईएलआर 2004 केएआर 2471]

फाउलर बनाम ग्रेस में, [(1970) 114 सोल जो 193 (सीए)] एडमंड डेविस, एल.जे., ने कहा है कि:

"यह न्यायाधिकरण का स्पष्ट कर्तव्य है कि वह अपनी शक्ति के भीतर यथासंभव पूर्ण राशि दे। ऐसे कई नुकसान हैं जिन्हें आसानी से पैसे के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता है। यदि कोई व्यक्ति किसी दुर्घटना में अपनी दृष्टि, श्रवण खो देता है या खो देता है गंध संकाय या अंग, इस तरह के अभाव के मूल्य का आकलन बाजार मूल्य के संदर्भ में नहीं किया जा सकता है क्योंकि दुर्घटना में खोई गई व्यक्तिगत संपत्ति के लिए कोई बाजार मूल्य नहीं है, और पैसे के संदर्भ में इसके समकक्ष व्यक्त करने का कोई आसान तरीका नहीं है।"

41. मैकग्रेगर ऑन डैमेज (14 वां संस्करण) पैरा 1157 में, व्यक्तिगत चोट कार्यों में क्षति के प्रमुखों का जिक्र करते हुए, निम्नानुसार बताता है:

"शारीरिक रूप से घायल व्यक्ति अपने आर्थिक नुकसान और गैर-आर्थिक नुकसान दोनों की भरपाई कर सकता है। इनमें से आर्थिक नुकसान में दो अलग-अलग चीजें शामिल हैं, अर्थात् कमाई और अन्य लाभ का नुकसान जो वादी को होता यदि वह घायल नहीं हुआ होता और चोट के परिणामस्वरूप उसे होने वाले चिकित्सा और अन्य खर्च, और अदालतो ने गैर-आर्थिक हानियों को तीन श्रेणियों में विभाजित किया गया है यानि कि दर्द और पीड़ा, जीवन की सुविधाओं की हानि और जीवन की उम्मीद की हानि।

इसके अलावा, न्यायालय को यह याद रखने की सलाह दी जाती है कि इन सभी मामलों में क्षति के उपाय 'ऐसे होने चाहिए कि एक अत्याचारी भी यह कह सके कि उसने अपने दुस्साहस के लिए पर्याप्त प्रायश्चित कर लिया है।' लॉर्ड डेवलिन का अवलोकन कि समस्या के

प्रति उचित दृष्टिकोण या एक परीक्षण अपनाना कि समकालीन समाज किसे निष्पक्ष सुरन समझेगा। जैसे कि गलत काम करने वाले को 'अपने पड़ोसियों के बीच अपना सिर उठाकर उनकी सहमति से यह कहने की इजाजत होगी कि उसने उचित काम किया है', यह व्यक्तिगत चोट के मामलों में मुआवजे का आकलन करते समय न्यायालय द्वारा ध्यान में रखा जाना काफी उपयुक्त है।"

(जोर दिया गया)

42. आर. वेंकटेश बनाम पी. सरवनन में कर्नाटक उच्च न्यायालय ने एक व्यक्तिगत चोट के मामले से निपटते समय, जिसमें दावेदार को कुछ कुचलने वाली चोटें लगीं, जिसके कारण उसका बायां निचला अंग कट गया था, यह माना गया कि कार्यात्मक विकलांगता के संदर्भ में, दावेदार को पहुंची विकलांगता कुल और 100% बरकरार रखा गया है, हालांकि दावेदार का केवल बायां निचला अंग काटा गया था। फैसले के पैरा 9 में, न्यायालय ने निम्नानुसार कहा: (कांत एलजे पृष्ठ 415)

'9. विच्छेदन के परिणामस्वरूप, दावेदार को अपंग बना दिया गया था। चलने के लिए भी उसे बैसाखी का सहारा लेना पड़ता है। वह किसी भी प्रकार के शारीरिक कार्य के लिए अयोग्य हो गया है। चूँकि वह पहले एक लोडर था और हाथ से काम करता था, घुटने के नीचे से उसका बायाँ पैर कट जाने के कारण वह किसी भी तरह के शारीरिक काम के लिए अयोग्य हो गया है। उसके पास कोई शिक्षा नहीं है। ऐसे मामलों में, यह अच्छी तरह से तय है कि आर्थिक और कार्यात्मक विकलांगता को संपूर्ण माना जाएगा, भले ही शारीरिक विकलांगता 100% न हो।'

43. बेकर बनाम विलॉबी में लॉर्ड रीड ने कहा है: (एसी पृष्ठ 492 ए)

"...किसी व्यक्ति को शारीरिक चोट के लिए मुआवजा नहीं दिया जाता है: उसे उस नुकसान के लिए मुआवजा दिया जाता है जो उसे उस चोट के परिणामस्वरूप होता है। उसका नुकसान पैर में अकड़न होने से नहीं है: यह पूर्ण जीवन जीने में उसकी असमर्थता में है, उन सुविधाओं का आनंद लेने में उसकी असमर्थता जो आवाजाही की स्वतंत्रता पर निर्भर करती है और उतना कमाने में असमर्थता है जितना वह कमाता था या कमा सकता था...।"

19. उपरोक्त संदर्भित मामलों में इस न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून के मद्देनजर, जिन पर व्यापक रूप से विचार किया गया है और उचित और उचित मुआवजा दिया गया है, हमारे विचार में, उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश के फैसले में दिया गया 60 लाख रुपये का मुआवजा, जिसमें से 30 लाख रुपये अपीलकर्ता के नाम पर संयुक्त रूप से जमा किए जाने थे, जिसका प्रतिनिधित्व उसके माता-पिता प्राकृतिक अभिभावक के रूप में करते थे और मुख्य अभियंता या उसके नामांकित व्यक्ति प्रतिवादी-निगम का प्रतिनिधित्व करते थे। उसके वयस्क होने तक किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में सावधि जमा जमा करना न्यायसंगत और उचित है, लेकिन हमें विद्वान एकल न्यायाधीश के फैसले के उस हिस्से को रद्द करना होगा जिसमें निर्देश दिया गया था कि यदि वह जीवित रहता है, तो उसे राशि निकालने की अनुमति है, अन्यथा जमा राशि उत्तरदाताओं को वापस कर दी जाएगी क्योंकि यह कानूनी और वैध नहीं है क्योंकि एक बार अदालत द्वारा मुआवजा राशि दिए जाने के बाद, इसे दावेदार/अपीलकर्ता के पास जाना चाहिए। इसलिए, पीड़ित/दावेदार कानूनी रूप से इस न्यायालय द्वारा मामलों की श्रृंखला में निर्धारित सिद्धांतों/मार्गदर्शक कारकों के अनुसार अपने पक्ष में मुआवजा पाने के हकदार हैं, विशेष रूप से, कुणाल साहा के मामले में, जिसे ऊपर संदर्भित किया गया है। इसलिए, मोटर वाहन न्यायाधिकरण/उपभोक्ता

मंच/राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग/राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग या उच्च न्यायालयों द्वारा दिया गया मुआवजा पूरी तरह से ऐसे पीड़ितों/दावेदारों का होगा। यदि दावेदारों की मृत्यु हो जाती है, तब पीड़ित/दावेदारों या कानूनी प्रतिनिधियों के कानूनी उत्तराधिकारियों द्वारा ऐसी संपत्ति पर उत्तराधिकार के लिए उनके संबंधित धर्म का उत्तराधिकार अधिनियम लागू होगा, जैसा कि वे वसीयत को निष्पादित करने के लिए चुनते हैं, जिसमें उनकी इच्छा का संकेत मिलता है कि उनकी मृत्यु के बाद संपत्ति किसके पास जाएगी। उपरोक्त कारणों से, हम उप-पैरा (v) में निहित विद्वान एकल न्यायाधीश के निर्देश के उस हिस्से को जिसमें रूपये 30 लाख का मुआवजा अपीलकर्ता के पक्ष में दिया जाना, यदि वह वयस्क होने के समय जीवित नहीं है, तो अपीलकर्ता के माता-पिता को 5 लाख रुपये का भुगतान करने के बाद वह प्रतिवादी-निगम को वापस कर दिया जाएगा, पूरी तरह से अस्थिर है और अपास्त किये जाने योग्य है। तदनुसार, हम इसे अपास्त करते हैं और आदेश के मुख्य भाग में बताए अनुसार इसे संशोधित करते हैं।

20. शेष मुआवजा राशि रूपये याचिकाकर्ता (नाबालिग) के नाम पर रमन के माता-पिता और प्रतिवादी-निगम का प्रतिनिधित्व करने वाले इंजीनियर-इन-चीफ या उसके नामांकित व्यक्ति की संयुक्त संरक्षकता के तहत राष्ट्रीयकृत बैंक में कॉर्पस फंड के रूप में 30 लाख रूपये जमा किये जाने है, जिसमें से रूपये 20 हजार प्रतिमाह का ब्याज विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश के उप-पैरा (vi) में बताए गए खर्चों के प्रति, यह नहीं कहा जा सकता है कि यह अधिक है, लेकिन हमारे विचार में, दिए गए मुआवजे की उक्त राशि कम है और उचित नहीं है। अपीलकर्ता द्वारा झेली गई 100% स्थायी विकलांगता की प्रकृति के संबंध में, यह बहुत अधिक होनी चाहिए थी क्योंकि अपीलकर्ता को एक परिचारक की स्थायी सहायता, उपचार शुल्क की आवश्यकता होती है क्योंकि वह पीड़ा और वैवाहिक जीवन के नुकसान से पीड़ित है,

जिसकी भरपाई उच्च न्यायालय के विद्वान न्यायाधीश द्वारा दी गई मुआवजे की राशि से नहीं की जा सकती है। इसलिए, मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, इस न्यायालय के लिए इस संबंध में विद्वान एकल न्यायाधीश के फैसले को बहाल करना युक्तियुक्त और उचित होगा और हम मानते हैं कि उक्त निर्णय में निहित निर्देश उपर दर्शाये गये हद तक उचित हैं। खंडपीठ को अपने अपीलीय क्षेत्राधिकार का प्रयोग करते समय अपीलकर्ता की ओर से वकील द्वारा प्राप्त कथित अपेक्षित निर्देशों को स्वीकार नहीं करना चाहिए था और इसे विज्ञापन के रूप में नहीं मानना चाहिए था और एकल न्यायाधीश द्वारा उप मद संख्या 6 में प्रदान की राशि को संशोधित किया जाना चाहिये था और अपने फैसले में पैरा 4 को प्रतिस्थापित किया है जैसा कि निर्णय के पूर्वोक्त भाग में दर्शाया गया है जो पूरी तरह से अनुचित है और इसलिए, यह कानून में अस्थिर है क्योंकि यह उत्तरदाताओं की ओर से लापरवाही के लिए उचित और उचित मुआवजे का कानूनी अधिकार प्राप्त करने के अपीलकर्ता के अधिकार को प्रभावित करेगा।

21. उपरोक्त कारणों को ध्यान में रखते हुए, प्रतिद्वंद्वी कानूनी विवादों पर विचार करने के बाद और बिजली के झटके से हुई दुर्घटना में अपीलकर्ता को 100% स्थायी विकलांगता का सामना करना पड़ा, जिसके कारण उसने सभी सुविधाएं खो दीं और जीवन भर मृतप्राय हो गया, और विज्ञापन देने के बाद अपीलकर्ता के पक्ष में न्यायसंगत और उचित मुआवजा देने के लिए पालन किए जाने वाले मार्गदर्शक सिद्धांतों के संबंध में इस न्यायालय द्वारा मामलों की श्रेणी में निर्धारित कानून के आधार पर, हम निम्नलिखित आदेश पारित करते हैं:-

(1) विशेष रूप से उच्च न्यायालय की खंडपीठ के आक्षेपित निर्णय और आदेश के उप पैरा (vi) के स्थान पर विद्वान एकल न्यायाधीश के आदेश के प्रतिस्थापित

पैराग्राफ संख्या 4 को अलग करने के बाद अपील की अनुमति दी जाती है। इस निर्णय में हमारे द्वारा निम्नलिखित संशोधनों के साथ।

(II) हम विद्वान एकल न्यायाधीश के आदेश के उप-पैरा (v) और (vi) में दिए गए मुआवजे को बहाल करते हैं:

(ए) संशोधित रूप में मुआवजा प्रतिवादियों को अपीलकर्ता के वयस्क होने की आयु तक उसके पिता द्वारा प्राकृतिक अभिभावक के रूप में प्रतिनिधित्व किए गए राष्ट्रीयकृत बैंक में 30 लाख रुपये रखने के निर्देश के साथ दिया जाता है।

(बी) विद्वान एकल न्यायाधीश के फैसले में आगे की दिशा यह है कि यदि अपीलकर्ता वयस्कता की आयु प्राप्त करने के समय जीवित नहीं है, जमा राशि उत्तरदाताओं को वापस कर दी जाएगी, अपास्त किया जाता है।

(सी) हम आगे घोषणा करते हैं कि 30 लाख रुपये के मुआवजे की उक्त राशि विशेष रूप से अपीलकर्ता की है और उनके निधन के बाद इसे कानूनी उत्तराधिकारियों या प्रतिनिधियों के पास जाना चाहिए क्योंकि यह अपीलकर्ता की विशेष संपत्ति है क्योंकि यह मुआवजा है उत्तरदाताओं की लापरवाही के कारण बिजली के झटके के कारण हुई 100% स्थायी विकलांगता के लिए उन्हें यह पुरस्कार दिया गया। उसके अवयस्क होने की अवधि के दौरान अर्जित मासिक ब्याज अपीलकर्ता के अभिभावक द्वारा वापस ले लिया जाएगा और उसे अपने मासिक खर्चों के लिए खर्च किया जाएगा और उसके वयस्क होने के बाद, उसके लिए यह खुला है कि वह या तो जमा जारी रखे या उसे वापस ले ले। यदि वह जीवित नहीं रहता है तो उसके या उसके कानूनी उत्तराधिकारियों या कानूनी प्रतिनिधि के लिए उपयुक्त है।

(डी) विद्वान एकल न्यायाधीश के फैसले के उप-पैरा (vi) में निर्देशित कॉर्पस राशि के रूप में 30 लाख रूपये की जमा राशि अपीलकर्ता के नाम पर होंगे, जो उसके

वयस्क होने तक विशेष रूप से उसके प्राकृतिक अभिभावकों/माता-पिता द्वारा प्रतिनिधित्व किया जाएगा, जो आय अर्जित की जाएगी, ऐसी जमा राशि माता-पिता द्वारा व्यक्तिगत खर्चों के लिए हर महीने निकाली जा सकती है। जिस बैंक में मुख्य अभियंता के नाम पर जमा किया गया है, उसे हटा दिया जाएगा और अपीलकर्ता का नाम ऊपर बताए अनुसार दर्ज किया जाएगा। वयस्कता की आयु प्राप्त करने के बाद, अपीलकर्ता उपरोक्त राशि को वापस लेने के लिए भी स्वतंत्र है। यदि किसी कारण से अपीलकर्ता जीवित नहीं रहता है, तो उसके उत्तराधिकारी/कानूनी प्रतिनिधि उक्त राशि वापस ले सकते हैं।

(ई) अनुपालन के लिए उत्तरदाताओं को विद्वान एकल न्यायाधीश के फैसले में अन्य निर्देश वैसे ही रहेंगे, उनका अनुपालन किया जायेगा तथा रिपोर्ट विद्वान एकल न्यायाधीश के समक्ष प्रस्तुत की जाएगी।

उपरोक्त शर्तों के तहत अपील को स्वीकार किया जाता है, लेकिन बिना किसी लागत के।

निधि जैन

अपील स्वीकार की गई।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल सुवास की सहायता से अनुवादक अधिवक्ता नृपेन्द्र सिनसिनवार द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण : यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिये स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उददेश्य के लिये इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उददेश्यो के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उददेश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।